जिला सूचना कार्यालय हरिद्वार।
निकट देवपुरा चौक, पुरानी कचहरी, हरिद्वार।
E-mail: suchnaharidwar@gmail.comदूरभाष/फैक्स : 01334–226695, मोबाइलः 9412074595
दिनांक : 03.02.2018

प्रेस विज्ञप्ति

हरिद्वार। जिलाधिकारी दीपक रावत ने ग्राम इमलीखेड़ा, लिब्बरहेड़ी तथा तहसील रूड़की का स्थलीय भ्रमण किया। इमलीखेड़ा में जिलाधिकारी सीडीओ स्वाती भदौरिया की पहल पर मनरेगा योजना के अन्तर्गत बनाये गये आंगनबाड़ी भवनों को पेंटिग फेस्टिवल के माध्यम से आकर्षक बनाने के लिए आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। जहां डीएम, सीडीओ, डीडीओ, डीपीआरओ सहित कई कॉलेज, स्कूलों के छात्रों व ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी केंद्र की दीवारों पर पेंटिग की। सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग को सीडीओं की ओर से पुरस्कृत किया जायेगा। जिलाधिकारी ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक केंद्र में कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों की लगातार जांच की जाये तथा पोषाहार से भी सुधार न हो पाने वाले बच्चों को हरिद्वार शहर में बने न्यूट्रिशन सेंटर तक पहुंचाने का कार्य माता–पिता की सहमति तैयार कर किया जाये। इस सेंटर में रहने वाले बच्चों को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए पूर्ण खर्च सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

इसके बाद जिलाधिकारी लिब्बरहेड़ी गांव पहुंचें। गांव में जिलायोजना, राज्य सैक्टर, केंन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत हुए विकास कार्यो का स्थलीय निरीक्षण किया। जिसमें 31 लाख की धनराशि एक ही सड़क निर्माण में खर्च कर दिये जाने की, 80 स्ट्रीट लाइटों की जगह मात्र 35 स्ट्रीट लाइटें लगाने, कूड़ेदान न पाये जाने जैसी अनियमितता पर डीएम ने प्रधान के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश डीपीआरओ को दिये।

जिलाधिकारी ने शिविर के माध्यम से ग्रामीणों की समस्यायें भी सुनीं। ग्रामीणों ने जमीनों की चकबंदी समय पर न किये जाने को गांव की सबसे बड़ी समस्या बताया। उन्होंने कहा कि सीमांकन में पटवारियों द्वारा रकबा छोटा दिखाना भी ग्रामीणों के लिए बड़ी समस्या बन गया है। डीएम ने चकबंदी अधिकारी को छुटी हुई जमीनों की चकबंदी अतिशीघ्र कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये, साथ ही ग्रामीणों को भी बिना विवाद चकबंदी सहयोग करने की अपील की। शिविर में आये फरियादियों ने राशन कार्ड बनाये जाने, दिव्यांग पेंशन, शौचालय निर्माणा , सड़कों की जल निकासी की समस्या डीएम के सामने रखी। जिनको सम्बंधित विभागों को निर्धारित समय में समाधान किये जाने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिये।

जिलाधिकारी ने रूड़की तहसील पहुंचकर तहसील का वार्षिक अनुश्रवण भी किया। डीएम ने रूड़की तहसील का स्पष्ट रंगीन नक्शा, लेखपालों के पदों की स्थिति, संग्रह अमीनों द्वारा वसूली की खराब स्थिति व अनुश्रवण में अनुपस्थित कर्मचारियों के वेतन रोकने, स्पष्टीकरण तलब किये जाने के निर्देश ज्वाइंट मजिस्ट्रेट निकिता खण्डेलवाल को दिये।

जिलाधिकारी ने कारगुजारी रजिस्ट्रर, छठ वार्षिक रोस्टर, मुख्यमंत्री राहत कोष, आपदा राहत कोष, नामांतरण पंजिका आदि की भी समीक्षा की। लक्ष्य में सबसे कम वसूली वाले लेखपालों को 31 मार्च तक 80 प्रतिशत वसूली लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिये।

जिला सूचना अधिकारी,
हरिद्वार।